आकाशवाणी
देहरादून (उत्तराखण्ड)

मंगलवार 02.02.2026 समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- केंद्रीय बजट में उत्तराखंड को मिला रेल परियोजनाओं के लिए 4,769 करोड़ रुपये का बजट। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा– बजट के रिकॉर्ड आवंटन से राज्य में रेलवे अवसंरचना को नई गति मिलेगी।
- हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन जोखिम और सुरक्षित विकास पर देहरादून में अंतरराष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू।
- रुद्रप्रयाग ज़िले में क्षय रोग के संपूर्ण उन्मूलन के लिये स्वास्थ्य विभाग का 100 दिवसीय विशेष निःक्षय शिविर अभियान शुरु।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा –राज्य में कानून व्यवस्था और जनसेवा को लेकर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

रेल परियोजना बजट

बजट में उत्तराखंड को रेल परियोजनाओं के लिए 4 हजार 769 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026–27 के लिए यह अब तक का रिकॉर्ड आवंटन है, जो वर्ष 2014 से पहले के औसत आवंटन की तुलना में 26 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में कुल 39 हजार 491 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे राज्य में रेलवे अवसंरचना को नई गति मिलेगी।

रेल मंत्री कल देहरादून स्थित पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित वर्चुअल पत्रकार वार्ता में उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों के पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। श्री वैष्णव ने बताया कि राज्य में नए रेल ट्रैक निर्माण, स्टेशनों के पुनर्विकास और सुरक्षा से जुड़े कई कार्य प्रगति पर हैं। अमृत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के 11 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप में विकसित किया जा रहा है, जिन पर 147 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए राज्य में इस समय तीन वंदे भारत एक्सप्रेस और एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन हो रहा है। रेल नेटवर्क विस्तार की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से उत्तराखंड में लगभग 76 किलोमीटर नए रेल ट्रैक का निर्माण किया गया है। राज्य में शत प्रतिशत रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य भी हासिल कर लिया गया है। इसके तहत 334 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण, 106 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण तथा सुरक्षा के लिए 54 कवच सिस्टम को स्वीकृति दी गई है। एक प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री ने कहा कि अमृत स्टेशन योजना के तहत हरिद्वार रेलवे स्टेशन को उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप विशेष डिजाइन में विकसित किया जाएगा, ताकि यात्रियों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। आकाशवाणी देहरादून के लिये समाचार कक्ष से अमित सुन्द्रियाल

मंथन

हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन के बढ़ते खतरे और सुरक्षित विकास को लेकर देहरादून में मंथन शुरू हो गया है। उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की ओर से हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में आपदा–सक्षम विकास विषय पर आयोजित पांच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम 2 से 6 फरवरी तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण एवं वित्तीय प्रशासन अनुसंधान संस्थान, सुद्धोवाला में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश–विदेश के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट–

कार्यक्रम के उद्घाटन पर आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है और यहां विभिन्न आपदाओं की आशंका बनी रहती है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य भूस्खलन जोखिम को वैज्ञानिक रूप से समझना, सुरक्षित अवसंरचना विकसित करना और आपदा पुनर्बहाली तंत्र को मजबूत करना है।

कार्यशाला में नॉर्वे के भू–तकनीकी संस्थान के विशेषज्ञ ढलान स्थिरता, सॉइल नेलिंग, जल निकासी और उपग्रह आधारित जोखिम मानचित्रण पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। वहीं, भूस्खलन विशेषज्ञ डॉ. हाकोन हेयर्डल ने वैज्ञानिक अध्ययन, बेहतर पूर्व चेतावनी और अंतरराष्ट्रीय अनुभव साझा करने की आवश्यकता बताई। विश्व बैंक प्रतिनिधि अनुप करण्थ ने कहा कि 2013 की आपदा के बाद से उत्तराखण्ड में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर लगातार सहयोग किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों ने हरिद्वार स्थित मनसा देवी भूस्खलन क्षेत्र का क्षेत्रीय भ्रमण भी किया, जहां वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर जोखिम विश्लेषण और न्यूनीकरण उपायों का व्यावहारिक अध्ययन कराया गया।

कार्यशाला में यूएलएमएमसी, यूएसडीएमए, नेपाल, भूटान सहित विभिन्न संस्थानों के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए। आकाशवाणी देहरादून के लिये समाचार कक्ष से डॉ० विनोद पोखरियाल

निक्षय शिविर अभियान

रुद्रप्रयाग ज़िले में क्षय रोग के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से 100 दिवसीय विशेष नि–क्षय शिविर अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत फरवरी और मार्च माह में आयोजित होने वाले शिविरों का रोस्टर भी जारी कर दिया गया है।

जिला क्षय अधिकारी डॉ. कुणाल चौधरी ने बताया कि अभियान के दौरान टीबी के लिहाज से संवेदनशील और उच्च जोखिम वाली आबादी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें पूर्व टीबी मरीज, टीबी रोगियों के घरेलू संपर्क, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, कुपोषित लोग, धूम्रपान करने वाले, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति और टीबी के लिए चिन्हित गांवों की 14 वर्ष से अधिक आयु की आबादी को शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि शिविरों के माध्यम से टीबी मरीजों की सक्रिय खोज की जाएगी, जिसमें स्क्रीनिंग, एक्स–रे और बलगम जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही रोग की समय पर पहचान, उपचार की शीघ्र शुरुआत और पोषण सहायता योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा, ताकि टीबी उन्मूलन से जुड़ी सेवाएं प्रभावी रूप से आमजन तक पहुंच सकें।

कानून व्यवस्था व जनसेवा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था और जनसेवा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही अब स्वीकार नहीं की जाएगी। सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस, प्रशासन और अन्य विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि आम आदमी के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार हो तथा कानून व्यवस्था से कोई समझौता न किया जाए।

पुलिस व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने थानों में वर्क कल्चर सुधारने और निर्दोष लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न करने के निर्देश दिए। रात्रि गश्त बढ़ाने, लगातार पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने और

आपराधिक मामलों की विवेचना में देरी न करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने भूमि से जुड़े अपराधों पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए लैंड फ्रॉड के मामलों में सख्त कानून बनाने और दोषियों को किसी भी तरह की राहत न देने के निर्देश दिए।

नशा मुक्ति को जन आंदोलन के रूप में चलाने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले से मासिक रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस वे के खुलने के बाद राज्य में पर्यटन बढ़ेगा, इसलिये इसे देखते हुए होटल, आवास, पार्किंग, ट्रैफिक और सुरक्षा से जुड़ी सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। उन्होंने बताया कि कैंची धाम बाईपास जून तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने जनशिकायत निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए 1905 हेल्पलाइन पर जीरो पेंडेंसी का लक्ष्य तय किया। साथ ही मुख्यमंत्री घोषणाओं के 100 प्रतिशत क्रियान्वयन, योजनाओं के भौतिक सत्यापन और गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव सहित सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आकाशवाणी देहरादून के लिये समाचार कक्ष से सिमरन बिंजोला

कानून व्यवस्था

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव ने अभियोजन और फॉरेंसिक जांच व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि इनकी प्रगति और निगरानी प्रभावी होनी चाहिए। आमजन की शिकायतों के निस्तारण को लेकर उन्होंने हेल्पलाइन 1905 पर प्राप्त शिकायतों की जिलाधिकारी और एसएसपी स्तर पर नियमित निगरानी के निर्देश दिए। साथ ही थाना और तहसील दिवस के माध्यम से गृह और पुलिस विभाग से जुड़े मामलों के निस्तारण की बात कही और इसके लिए संबंधित विभागों को मिलकर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने थानों में जब्त वाहनों की नीलामी कर स्थान खाली कराने पर भी जोर दिया और न्यायालयों में लंबित मामलों से जुड़े वाहनों के निस्तारण के लिए संभावनाओं को तलाशने को कहा। उन्होंने पॉक्सो मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साइबर अपराध पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ–साथ जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएं। बैठक में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में विकास कार्यों की ज़िलावार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को जनपद, खंड और पंचायत स्तर पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर के 2047 विजन डॉक्यूमेंट की तर्ज पर स्थानीय स्तर पर भी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र कार्य किया जाए और इसके लिए आवश्यक कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिला योजना समितियों की बैठकें मार्च तक अनिवार्य रूप से करा ली जाएं और अभी से तैयारियां शुरू की जाएं, ताकि योजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके।

श्री बर्द्धन ने उद्यान, कृषि और पशुपालन विभागों में ज़िला स्तर पर खरीद से जुड़ी शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया और मूल्य निर्धारण को एक वर्ष के बजाय दो से तीन वर्ष के लिए तय करने जैसे उपायों पर भी विचार करने को कहा। आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जिला योजना की गाइडलाइन में आवश्यक सुधार करने पर भी जोर दिया गया।

आजिविका से जुड़ी योजनाओं को गंभीरता से लेने पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इनकी जिला स्तर पर मासिक समीक्षा और राज्य स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने राजकीय महिला विद्यालयों को 8 मार्च 2026 तक शौचालय निर्माण से संतृप्त करने और उनकी सफाई व्यवस्था के लिए ठोस योजना बनाने के निर्देश भी दोहराए।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर...

मुख्यमंत्री धामी ने कहा– कार्यशैली सुधाने पुलिस, आम आदमी को सताया न जाए– अमर उजाला इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है– मुकदमों में कमजोर पैरवी बर्दाश्त नहीं, अभियोजन अधिकारियों का परफॉर्मेंस ऑडिट कराने के निर्देश।

अंकिता मर्डर केस में सीबीआई दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच में मुकदमा दर्ज– दैनिक जागरण इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है– वीआईपी का पता लगाने उत्तराखंड पहुंची सीबीआई की टीम, दून व ऋषिकेश में जांच।

वन भूमि के सर्वे के विरोध में सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग– हिन्दुस्तान समाचार परत्र इस हेडलाइन के साथ खबर में लिखता है– ऋषिकेश में बापूग्राम बचाओ संघर्ष समिति ने भरी हुंकार।

उत्तराखंड में 83 चोटियों पर पर्वतारोहण के लिए भारतीयों को अब कोई शुल्क नहीं देना होगा– दैनिक जागरण इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है– सीएम धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने की पहल।